

मैसर्स मोटर इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड

बनाम

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, औरंगाबाद।

20 जनवरी 2006

[अशोक भान और एस.एच. कपाडिया, जे.जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985-अध्याय 84-इंजेक्टर के युग्मन में उपयोग किए जाने वाले नोजल और नोजल धारक-छूट-अधिकरण और अधिकारियों द्वारा इंजेक्टर के निर्माण और घटकों के बारे में निर्णय लेने में विफलता-विभाग इस बात का सबूत पेश करने में असफल रहा कि नोजल और नोजल धारक मध्यवर्ती थे, उत्पाद जो युग्मन पर इंजेक्टर बन गए, और विपणन योग्य थे - निर्धारिती भी छूट के लिए अपनी पात्रता साबित करने में विफल रहे, इस प्रकार, मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को भेज दिया गया।

अपीलकर्ता-निर्धारिती नोजल, नोजल होल्डर और इंजेक्टर के निर्माण में लगा हुआ है। विभाग ने अपीलकर्ताओं को इंजेक्टरों के संबंध में नोजल और नोजल धारकों पर शुल्क लगाने के लिए नोटिस जारी किया क्योंकि टैरिफ आइटम 8409.00 के तहत आने वाले नोजल और

_नोजल धारक 8409.00 के तहत आने वाले इंजेक्टरों (अंतिम उत्पाद) के युग्मन या संयोजन में उपयोग किए जाने वाले मध्यवर्ती उत्पाद थे और कपलिंग की प्रक्रिया पूरी होने पर एक नया स्वतंत्र उत्पाद सामने आया, जिसका नाम था इंजेक्टर। अपीलकर्ता ने *केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर बनाम मोटर इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड के मामले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि इंजेक्टर नोजल धारकों में नोजल का एक फिटमेंट था और युग्मन पर कोई नया उत्पाद अस्तित्व में नहीं आया; और अधिसूचनाओं द्वारा गैर-वाहन इंजेक्टर और वाहन नोजल और नोजल धारकों को शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी। ट्रिब्यूनल ने माना कि निर्धारित अधिसूचना के तहत छूट का हकदार नहीं था क्योंकि नोजल और नोजल धारकों को विशेष रूप से बाहर रखा गया था और मोटर इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड का मामला लागू नहीं था। इसलिए वर्तमान अपील।

मामले को निर्णायक प्राधिकारी को भेजते हुए, न्यायालय ने कहा:

न्यायाधिकरण सहित नीचे के प्राधिकारियों ने यह निर्णय नहीं लिया कि इंजेक्टर का निर्माण कैसे किया जाता है और इसके घटक क्या हैं। निर्माण और विपणन क्षमता पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का बोझ विभाग पर था, जिसका उसने पालन नहीं किया। साथ ही अपीलकर्ता पर यह साबित करने का भार भी था कि वे अधिसूचना के तहत छूट

के हकदार थे। निर्माण, वर्गीकरण और छूट का प्रश्न आपस में जुड़ा हुआ है। छूट का प्रश्न कपलिंग या असेंबली पर पहला प्रश्न तय होने के बाद ही उठेगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के बाद संशोधित छूट अधिसूचनाओं को देखा जाना चाहिए और वाहन और गैर-वाहन उपयोगकर्ताओं के लिए इंजेक्टरों की असेंबली के आवेदन की भी 1985 अधिनियम के आलोक में जांच की जानी चाहिए। उस संबंध में एचएसएन की सहायता भी ली जा सकती है। [1494-बी-सी; ई-जी]

*केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर बनाम मोटर इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, (1989) 43 ईएलटी 290, अस्वीकृत।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4391-4392/2000 (अपील संख्या ई/4495/89-बी और ई/5550/91 में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश संख्या 601-602/2000-बी दिनांक 20.4.2000 से) अपीलकर्ता के लिए जोसेफ वेल्लापल्ली, यू.ए.राणा, संदीप खरेल, सुश्री एस. राँय और मेसर्स गगराट एंड कंपनी के लिए अग्वेश सिंह।

प्रतिवादी की ओर से मोहन परासरन, एएसजी, मनीष शर्मा और पी. परमेश्वरन।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

कपाड़िया, जे.,

केंद्रीय धारा 35-एल(बी) के तहत निर्धारिती द्वारा दायर इन नागरिक अपीलों में निर्धारण के लिए संक्षिप्त प्रश्न उठता है। उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (बाद में इसे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) क्या नोजल की असेंबली और नोजल धारक (मध्यवर्ती उत्पाद) "इंजेक्टर" नामक एक नया उत्पाद अस्तित्व में लाते हैं और यदि हां, तो क्या विभाग उप-शीर्षक 8409.00 के तहत उक्त इंजेक्टर को वर्गीकृत करने में सही था।

अपीलकर्ता नोजल, नोजल होल्डर और इंजेक्टर के निर्माण में लगा हुआ है। कारण बताओ नोटिस दिनांक 3.9.1986 के माध्यम से, विभाग ने अपीलकर्ता को कारण बताने के लिए कहा कि नोजल और नोजल धारकों के मूल्य पर 20% यथामूल्य शुल्क इस आधार पर इंजेक्टरों के संबंध में क्यों नहीं वसूला जाना चाहिए कि अपीलकर्ता ने टैरिफ आइटम 8409.00 के अंतर्गत आने वाले नोजल और नोजल धारकों का उत्पादन किया था, जिनका उपभोग 8409.00 के तहत आने वाले इंजेक्टरों के निर्माण के लिए किया गया था, जिसके लिए

अपीलकर्ता द्वारा उनकी वर्गीकरण सूची में कोई घोषणा नहीं की गई थी। इस स्तर पर, हम बता सकते हैं कि इस मामले का इतिहास उतार-चढ़ाव वाला है, इसे कई बार रिमांड पर लिया गया है और इसके बाद उल्लिखित कारणों के लिए, पूर्व मुकदमेबाजी के पूरे इतिहास को बताना आवश्यक नहीं है। यह बताना पर्याप्त है कि कारण बताओ नोटिस के जवाब में, अपीलकर्ता ने कहा कि नोजल धारकों में नोजल की फिटिंग का निर्माण नहीं होता है; कि, इस तरह के फिटमेंट के बाद भी, अंतिम परिणाम "नोजल और नोजल होल्डर" ही रहा; कि, यह पूरा विवाद सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलकर्ता न्यायाधिकरण (संक्षेप में "न्यायाधिकरण") के पहले के फैसले से एक ही पक्ष के बीच, अर्थात् केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर बनाम मोटर इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड के मामले में सुलझाया गया था। ., (1989) 43 ईएल टी 290 में रिपोर्ट किया गया; कि, नोजल और नोजल होल्डर का कोई स्वतंत्र अनुप्रयोग नहीं था; कि, उन्हें आईसी इंजन के दहन कक्ष में दहन पैदा करने के लिए इकट्टे राज्य में आईसी इंजन में उपयोग किया जाना है। अपीलकर्ता के अनुसार, एक इंजेक्टर नोजल धारकों में नोजल का एक फिटमेंट था और युग्मन पर, कोई नया उत्पाद अस्तित्व में नहीं आया। जवाब में, अपीलकर्ता ने आगे कहा कि गैर-वाहन इंजेक्टरों को शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी। इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया कि गैर-वाहन डी' इंजेक्टर कृषकों और

किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले डीजल इंजन के हिस्से हैं और इसलिए, सरकार ने ऐसे गैर-वाहन इंजेक्टरों को छूट देने का निर्णय लिया है। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जा सकता है कि नोजल और नोजल धारकों को छूट अधिसूचना संख्या 217/85 दिनांक 8.10.1985 से बाहर रखा गया था। हालांकि, अपीलकर्ता के अनुसार, संशोधन अधिसूचना संख्या 79/86 दिनांक 10.2.1986 द्वारा, गैर-वाहन इंजेक्टरों को भी छूट का लाभ दिया गया था , जिसकी विभाग द्वारा सराहना नहीं की गई है (ए.सी. के समक्ष निर्धारिती द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियाँ देखें, मूल रिकॉर्ड की पेपरबुक के रनिंग पेज नंबर 145 पर)। इसी प्रकार, अपीलकर्ता के अनुसार, सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 75/86 दिनांक 10.8.1986 के तहत उत्पादन के कारखाने में उपयोग किए जाने वाले वाहन नोजल और नोजल धारकों को भी छूट दी गई थी। (ए.सी. के समक्ष निर्धारिती द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियाँ देखें, मूल रिकॉर्ड की पेपरबुक के चालू पृष्ठ संख्या 142 पर)।

आक्षेपित निर्णय द्वारा, ट्रिब्यूनल ने माना कि निर्धारिती उपरोक्त अधिसूचना संख्या 217/85 के तहत छूट का हकदार नहीं था क्योंकि "नोजल और नोजल धारकों" को विशेष रूप से उक्त अधिसूचना के दायरे से बाहर रखा गया था; कि, मोटर इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड

(सुप्रा) के मामले में मुद्दा केवल यह था कि क्या नोजल धारकों (इंजेक्टर) के साथ लगे नोजल पुराने टैरिफ के आइटम 68 के तहत मूल्यांकन योग्य थे, हालांकि नोजल और नोजल धारकों को आइटम 34 ए के तहत शुल्क का भुगतान किया गया था, इसलिए उस निर्णय का मौजूदा विवाद पर कोई प्रभाव नहीं था।

निम्नलिखित कारणों से इस मामले को निर्णायक प्राधिकारी को भेजे जाने की आवश्यकता है। सबसे पहले, इस मामले में, कारण बताओ नोटिस में विभाग का मामला यह था कि नोजल और नोजल धारक मध्यवर्ती उत्पाद थे जिनका उपयोग इंजेक्टर (अंतिम उत्पाद) के युग्मन या संयोजन में किया जाता था; और, युग्मन की प्रक्रिया पूरी होने पर एक नया स्वतंत्र उत्पाद सामने आया, जिसका नाम था, एक इंजेक्टर। इंजेक्टर का निर्माण कैसे किया जाता है और इसके घटक क्या हैं, इसका निर्णय ट्रिब्यूनल सहित नीचे किसी भी प्राधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। दूसरे, मोटर इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) में ट्रिब्यूनल का निर्णय लागू नहीं होता है। उस स्थिति में, प्रश्न यह उठता है कि 'ए' क्या है? इंजेक्टर समस्या में नहीं था. यह पुराने टैरिफ के तहत वर्गीकरण का मामला था जिसके तहत आइटम 34 ए "मोटर वाहन के हिस्सों" से संबंधित था और किन हिस्सों को विशेष रूप से "नोजल और नोजल धारकों" को शामिल करने के लिए वर्णित किया

गया था जबकि अवशिष्ट आइटम 'आइटम 68' था और सवाल यह था - क्या नोजल को होल्डर में फिट करने पर आइटम 68 लागू होगा। उक्त मामले में, यह माना गया कि फिटमेंट पर भी, उत्पाद आइटम 34 ए के तहत "नोजल और नोजल होल्डर" बना रहेगा। वर्तमान मामले में, विभाग द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि नोजल और नोजल होल्डर एक इंजेक्टर के घटक थे; युग्मन पर, जो प्रक्रिया निर्माण का गठन करती है, एक स्वतंत्र उत्पाद, अर्थात्, एक इंजेक्टर उभरा। यह बिंदु पहले के मामले में नहीं था, इसलिए, मोटर इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) का वर्तमान मामले में कोई आवेदन नहीं है। इसके अलावा, वर्तमान मामला 1985 टैरिफ अधिनियम के तहत उत्पन्न होता है, अध्याय 84 धारा XVI में आता है। शीर्षक 84.07, 84.08 और 84.09 के साथ अनुभाग नोट 2 पर विचार करना आवश्यक है। ये प्रावधान यहां मोटर इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में नहीं थे। तीसरा, इस मामले में, निर्माण और विपणन क्षमता पर साक्ष्य का नेतृत्व करने का बोझ विभाग पर था। यह साबित करना विभाग का काम है कि नोजल और नोजल होल्डर मध्यवर्ती उत्पाद थे जो युग्मन पर इंजेक्टर बन गए, जो बाजार में बिक्री योग्य वस्तु थी। पहले यह अभ्यास नहीं किया गया था क्योंकि विभाग ने यह माना था कि यह मुद्दा मोटर इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) द्वारा कवर किया गया था। अंत में, हम यह बता सकते हैं कि अपीलकर्ता ने उपरोक्त अधिसूचना

के तहत छूट का दावा किया है। उन पर यह साबित करने का बोझ है कि वे छूट के हकदार थे। इस संबंध में, हम बता सकते हैं कि छूट का प्रश्न कपलिंग या असेंबली पर पहला प्रश्न तय होने के बाद ही उठेगा। यहां हम यह भी बता सकते हैं कि 1985 टैरिफ अधिनियम के बाद संशोधित छूट अधिसूचनाओं को देखा जाना चाहिए। इस मामले में, निर्माण, वर्गीकरण और छूट का प्रश्न आपस में जुड़ा हुआ है। वाहन और गैर-वाहन उपयोगकर्ताओं के लिए उपरोक्त असेंबली के आवेदन की जांच 1985 टैरिफ अधिनियम के आलोक में की जानी है। उस संबंध में एचएसएन की सहायता भी ली जा सकती है।

उपरोक्त कारणों से, हम ट्रिब्यूनल के दिनांक 20.4.2000 के आक्षेपित फैसले को रद्द कर देते हैं और मामले को कारण बताओ नोटिस के नए फैसले के लिए निर्णायक प्राधिकरण को भेज देते हैं। तदनुसार, निर्धारिती द्वारा दायर उपरोक्त सिविल अपीलें लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के स्वीकार की जाती हैं।

एन.जे.

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।